भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 740

दिनांक 29.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके)

740. **डॉ. मन्ना लाल रावतः**

श्री बृजमोहन अग्रवालः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2014-24 के दौरान देश में खोले गए/कार्यरत पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पीएसके) की संख्या कितनी है तथा इसके लिए आवंटित धनराशि का वर्ष-वार और छतीसगढ़ एवं राजस्थान सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश भर में राजस्थान सहित राज्य-वार लंबित पासपोर्ट आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा आवेदनों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/प्रस्तावित हैं;

(घ) क्या सरकार के पास विशेष रूप से छतीसगढ़ के रायपुर लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में और अधिक पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ड.) क्या सरकार के पास उदयपुर के पीएसके संचालन को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में उन्नत करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार के पास छात्रों की सुविधा के लिए तत्काल पासपोर्ट जारी करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) भारत में कुल 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) और 442 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) खुले/कार्यरत हैं। पीएसके/पीओपीएसके की राज्य-वार और वर्ष-वार स्थापना अनुबंध-। पर दी गई है। पासपोर्ट संबंधी गतिविधियों के लिए वर्ष 2024-25 के लिए आवंटित बजट अनुमान 924.13 करोड़ है। इसमें टीसीएस, डाक विभाग, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, एसटीसी, आईएसपी नासिक को दिए जाने वाले सेवा शुल्क और 37 आरपीओ से संबंधित व्यय शामिल हैं।

(ख) पासपोर्ट जारी करने में लंबित मामले क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के अनुसार अनुरक्षित किए जाते हैं। लंबित मामलों की सूची अनुबंध-॥ पर संलग्न है।

(ग) मांग में वृद्धि के कारण, मंत्रालय पासपोर्ट जारी करने में तेजी लाने और पासपोर्ट की उच्च तथा व्यस्ततम-समय अनुसार मांग को पूरा करने के लिए लगातार काम करता रहा है, जिसमें दैनिक अपॉइंटमेंट की संख्या में वृद्धि और सप्ताहांत पर विशेष अभियान आयोजित करना शामिल है। विशेष अभियान के तहत लंबित मामलों को निपटाने के लिए मंत्रालय और अन्य क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के कर्मचारियों को भी तैनात किया जा रहा है।

सरकार ने पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को कई तरीकों से सरल बनाया है। पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल, उदार और आसान बनाने के लिए, मंत्रालय ने पासपोर्ट नीति को सरल बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिससे भारत के नागरिकों को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने और पासपोर्ट प्राप्त करने में लाभ हुआ है। पासपोर्ट पोर्टल (www.passportindia.gov.in) उपयोगकर्ता-अनुकूल है, जो भारत में कहीं से भी और कभी भी किसी के लिए भी सुलभ है। कोई भी आवेदक भारत में कहीं से भी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है। इस नागरिक-अनुकूल पहल ने आवेदकों को यह विचार किए बिना कि आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट वर्तमान आवासीय पता चयनित आरपीओ के अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं, ऐसे पासपोर्ट कार्यालय (पीओ) और इस प्रकार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) के तहत वांछित पीएसके/पीओपीएसके चुनने में सक्षम बनाया है, जहां वे अपना आवेदन जमा करना चाहते हैं। नागरिक एमपासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप पर पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट निर्धारित कर सकते हैं, और पासपोर्ट सेवाओं हेतु आवेदन

करने के लिए उन्हें कंप्यूटर और प्रिंटर की आवश्यकता नहीं है। एमपासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप उपयोगकर्ताओं को पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन करने, भुगतान करने और अपॉइंटमेंट निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। यह पासपोर्ट संबंधी जानकारी भी प्रदान करता है, जिसमें पीएसके/पीओपीएसके का स्थान, लागू शुल्क, जमा करने के तरीके और स्मार्ट फोन पर पासपोर्ट आवेदन की स्थिति को ट्रैक करना शामिल है। मंत्रालय के एमपासपोर्ट पुलिस ऐप का उपयोग पुलिस अधिकारियों द्वारा कागज रहित डिजिटल माध्यम से आवेदकों के पिछले रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए किया जा रहा है।

इसके अलावा, डिजिलॉकर को पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (पीएसपी) प्रणाली के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है, जिससे नागरिक पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवश्यक विभिन्न दस्तावेज़ों को डिजिलॉकर के माध्यम से कागज़ रहित तरीके से जमा कर सकते हैं। पासपोर्ट के शीघ्र जारी करने के लिए एक 'तत्काल योजना' है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने के लिए, सरकार ने पुरुष से महिला या महिला से पुरुष लिंग परिवर्तन के बाद पासपोर्ट में नाम और लिंग परिवर्तन के उद्देश्य से ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत जारी किए गए पहचान प्रमाण पत्र/पहचान पत्र को स्वीकार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

(घ) छत्तीसगढ़ के महासमुंद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अलावा प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (एलएससी) में एक पीएसके/पीओपीएसके है, क्योंकि वहाँ डाक विभाग (डीओपी) द्वारा आज तक कोई स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया है। मंत्रालय द्वारा अपने स्वीकृत बजट अनुदान से डाक विभाग को प्रत्येक पीओपीएसके की स्थापना के लिए 3 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है।

(ङ) मंत्रालय पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके), उदयपुर को पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) में उन्नत करने तथा इसे उन्नत एवं वर्धित सुविधाओं के साथ नए स्थान पर स्थानांतरित करने के संबंध में संबंधित हितधारकों के साथ गहन परामर्श कर रहा है।

(च) जहां तक छात्रों को शीघ्र पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने का संबंध है, वे अपेक्षित शुल्क का भुगतान करके तत्काल श्रेणी के अंतर्गत पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपेक्षित दस्तावेज पूरे करने के बाद, उनकी सुविधा के लिए पासपोर्ट शीघ्र जारी किया जाता है।

*****

अनुबंध 1

राज्यवार और वर्षवार पीएसके/पीओपीएसके की सूची

राज्य एवं संघ शासित प्रदेश	वर्ष																					
	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	पीएसके	पीओपीएसके	पीएसके	पीओपीएसके	पीएसके	पीओपीएसके	पीएसके	पीओपीएसके	पीएसके	पीओपीएसके	पीएसके	पीओपीएसके	पीएसके	पीओपीएसके	पीएसके	पीओपीएसके	पीएसके	पीओपीएसके	पीएसके	पीओपीएसके	पीएसके	पीओपीएसके
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह														1								
आंध्र प्रदेश	2				1			3		15		2										
अरुणाचल प्रदेश					1					2												
असम	1							1		11		3										
बिहार	1							5		11		17				1	1	1				
छत्तीसगढ़	1							1		4		2										2

राज्य एवं संघ शासित प्रदेश	वर्ष																					
	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	पीएसके	पीओपीएसके	पीएसके	पीओपीएसके	पीएसके	पीओपीएसके	पीएसके	पीओपीएसके	पीएसके	पीओपीएसके	पीएसके	पीओपीएसके	पीएसके	पीओपीएसके	पीएसके	पीओपीएसके	पीएसके	पीओपीएसके	पीएसके	पीओपीएसके	पीएसके	पीओपीएसके
दादरा एवं नगर हवेली								1														
दमन								1														
दिल्ली	4									4		1										
गोवा	1									1												
गुजरात	5							3		17		3										
हरियाणा								3		7		1										
हिमाचल प्रदेश	1							2		4												
जम्मू और कश्मीर	2							2		4												
झारखंड	1							2		5		7								1		

राज्य एवं संघ शासित प्रदेश	वर्ष																					
	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	पीएसके	पीओपीएसके	पीए सके	पीओ पीए सके	पीए सके	पी ओ पीए सके	पीए सके	पीओ पीए सके	पीए सके	पीओ पीए सके	पीए सके	पी ओ पीए सके	पीए सके	पीओ पीए सके	पीए सके	पीओ पीए सके	पीए सके	पीओ पीए सके	पीए सके	पीओ पीए सके	पीए सके	पीओ पीए सके
कर्नाटक	4						1	1		11		11										
केरल	13							2		3		2										
लक्षद्वीप								1														
मध्य प्रदेश	1						1	4		8		5		1						1		3
महाराष्ट्र	7						1	3		14		20				1		1		1		1
मणिपुर			1									1										
मेघालय			1							1												
मिज़ोरम			1																			
नागालैंड			1																			
ओड़ीशा	1							3		4		13										

राज्य एवं संघ शासित प्रदेश	वर्ष																					
	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	पीएस के	पीओपी एसके	पीए सके	पीओ पीए सके	पीए सके	पी ओ पीए सके	पीए सके	पीओ पीए सके	पीए सके	पीओ पीए सके	पीए सके	पी ओ पीए सके	पीए सके	पीओ पीए सके	पीए सके	पीओ पीए सके	पीए सके	पीओ पीए सके	पीए सके	पीओ पीए सके	पीए सके	पीओ पीए सके
पुडुचेरी										1												
पंजाब	7							2		3		4										
राजस्थान	3						1	5		11		8										
तमिलनाडु	8				1			2		8		19										
तेलंगाना	5		1					2		5		7										
त्रिपुरा												1										
उत्तर प्रदेश	6							6		24		18								1		2
उत्तराखंड	1									6												
पश्चिम बंगाल	2		2				1	4		11		25										
कुल योग	77	0	7	0	3	0	5	59	0	195	0	170	0	2	0	2	1	2	0	4	0	8

अनुबंध-II

आरपीओ अनुसार लंबित मामले (2014 – 31 अक्तूबर 2024)

आरपीओ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
सीपीवी दिल्ली	167	275	436	107	49	141	112	49	7	91	6
अहमदाबाद	6339	4586	1349	2440	9020	6162	3890	6966	4278	16818	3831
अमृतसर	1363	740	18	19	1199	1861	55	1302	643	4796	1223
बरेली	24474	17477	1756	3698	8508	19869	1851	12804	4882	12452	10666
बेंगलुरु	5289	1807	10913	12468	13215	5645	2609	4246	17597	10170	17851
भोपाल	2141	638	274	2402	1599	2343	1141	1888	460	871	1512
भुवनेश्वर	636	59	16	170	7755	7135	2238	1746	3464	5067	5174
चंडीगढ़	6870	2974	4446	6278	13915	9854	3101	13912	3077	18710	7346
चेन्नई	11553	4279	2483	2265	3542	4452	1675	1054	1855	1749	2032
कोचीन	370	598	285	127	143	233	97	155	844	627	462
कोयम्बटूर	383	106	106	1082	457	178	282	436	455	2724	4822
देहारादून	584	480	2284	322	11403	3200	2161	1386	782	3183	1166
दिल्ली	17946	24199	15519	10388	17136	40805	17485	16902	7573	8745	3534
गाज़ियाबाद	14339	7752	4834	8500	45912	9729	12118	17447	8095	21744	4576

आरपीओ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
गोवा	289	553	41	51	172	72	26	40	39	28	126
गुवाहाटी	2067	1304	576	393	3381	4381	566	1121	274	426	889
हैदराबाद	12785	3702	1702	770	638	2593	3145	11302	15044	5243	4674
जयपुर	4165	3873	2974	6313	5501	20630	4900	3812	2145	19200	7227
जालंधर	913	181	69	80	2	2	2	97	234	3363	2631
जम्मू	741	498	533	166	934	525	360	129	1022	1181	1619
कोलकाता	18632	5151	1829	1863	3991	42053	1247	5529	7995	2180	3131
कोटा*										1005	880
कोझिकोड	385	205	116	518	148	107	77	115	372	156	128
लखनऊ	4304	2590	2824	6574	21599	13638	4676	15999	3108	9513	14492
मदुरै	7111	2255	292	397	1451	1307	952	1817	1963	1567	2184
मलप्पुरम**	688	833	468	4	0						
मुंबई	7903	2444	1656	3879	16236	13555	3476	30091	2098	8230	7122
नागपुर	204	183	427	187	633	4270	3901	2618	1154	249	1793
पटना	16162	6339	11751	2447	44118	19741	3087	4847	269	2928	1461

आरपीओ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
पुणे	1810	1040	893	9267	22638	6135	861	2482	544	1023	805
रायपुर	166	54	155	388	2705	2317	680	571	215	1981	1929
रांची	37	314	212	449	2235	844	3630	375	287	2012	641
शिमला	60	29	20	779	615	274	16	49	4	348	1470
श्रीनगर	4001	831	687	560	768	843	1968	1041	4804	3286	1909
सूरत	1013	2407	2673	342	8725	2751	306	690	801	3192	7214
ठाणे***	2808	332	573	408	6						
तिरुचिरापल्ली	1649	790	1515	1744	1231	831	321	314	876	1323	553
तिरुवनंतपुरम	398	101	165	340	463	109	62	1946	1481	6589	737
विजयवाड़ा				2653	649	3824	1203	10735	7517	831	3700
विशाखापत्तनम	655	473	412	1132	1090	1045	117	7512	3147	1315	5404
कुल	181400	102452	77282	91970	273782	253454	84394	183525	109405	184916	136920

* आरपीओ कोटा का उद्घाटन 29 सितंबर 2023 को किया गया था।

** 20 नवंबर 2017 को आरपीओ मलप्पुरम का आरपीओ कोझिकोड में विलय कर दिया गया

*** 21 अगस्त 2017 को आरपीओ ठाणे का आरपीओ मुंबई में विलय कर दिया गया

*****